सम्पादक की कलम से

देश में पाँच राज्यों में चुनाव खत्म हो गए हैं और अगली मुकाबला केंद्र अब पक्के तौर पर उत्तर प्रदेश ही होगा। मुख्य मुकाबला बसपा और कांग्रेस में होगी, जबकि सपा और भाजपा नम्बर दो पर भूमिकाएं अदा करेंगी। अस्सी लोकसभा सांसदों और चार सौ तीन विधायकों का चुनाव करते समय राज्य के लोग भविष्य के प्रति आंखें नहीं बन्द करेगे इसलिए उनके मतदान को हाल ही में सम्पन्न पाँच राज्यों के विधानसभा चुनावों ने नतीजे अवश्य प्रभावित करेंगे।

कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही इन चुनावों से सबक मिला है कि राज्यों में चुनाव जीतना है तो मुख्यमंत्री अच्छा होना चाहिए। कांग्रेस के पास जहां असम में तरुण गोगोई और दिल्ली में शीला दीक्षित और हरियाणा में भूपिन्द्र सिंह हुड्डा हैं, वहीं भाजपा के पास गुजरात में नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और हिमाचल में प्रेम कुमार धूमल जैसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं। बिहार और उड़ीसा में भी क्रमश: नीतीश कुमार व नवीन पटनायक बढ़िया प्रशासन चला रहे हैं परन्तु यह बात ध्यान में रहनी चाहिए कि क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियों की कीमत पर सत्ता में आती हैं और ताजा चुनाव में एक अन्य राज्य पाण्डीचेरी भी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के हाथों में निकल गया है। उधर आंध्र प्रदेश में टीआरएस ने तेलंगाना आंदोलन पर पकड़ बनाई हुई है और वाईएसआर के पुत्र जगनमोहन ने बहुत बडें अंतर से कांग्रेस पर जीत दर्ज की है। उनके साथ टीडीपी की भी शक्ति मिलने से कांग्रेस को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना होगा।

गठबंधन सरकारों का दौर वास्तविकता यह है कि हम गठबंधन सरकारों वाले राजनीतिक दौर में जी रहे हैं और कोई भी केंद्रीय नेता किसी राज्य के चुनाव को तब तक प्रभावित नहीं कर सकता जब तक उनके पास राज्य स्तर पर कोई जादुई नेता न हो। केंद्र में सरकार का गठन विभिन्न पार्टियों के सदस्यों की संख्या का खेल है, जब कि राज्य स्तर पर चुनाव स्थानीय नेता के योग्यता और क्षमता पर निर्भर करते हैं। क्या यह रूझान भविष्य में भी जारी रहेगा? राज्यों के मतदाता स्थानीय नेताओं की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं और नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, जयललिता, रंगास्वामी, तरुण गोगोई सरीखे नेताओं की सफलता की उम्मीद करते हैं।

लोकसभा चुनाव अभी ३ वर्ष दूर हैं, और ताजा चुनाव में जीते व पराजित हुए पक्षों के लिए अपनी गलतियों को दुरुस्त करने का पर्याप्त समय है परंतु किसी तरह का दीर्घकालिक निष्कर्ष निकालना गलत होगा।

भारत-चीन ठोकेंगे अब आईएमएफ की अध्यक्षता का दावा अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक डोमिनिक स्ट्रॉस काह्व को यौन आक्रमण, बलात्कार के प्रयास के आरोपों में न्यूयार्क में गिरफ्तार करने के बाद अब जमानत पर रिहा कर दिया गया है।
यह 'भद्रपरुष' फ्रांस के राष्ट्रपति पद का मुख्य दावेदार था और वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी की तुलना में मत सर्वेक्षणों में भारी अंतर से आगे चल रहा था। जहां तक वर्ष २०१२ में होने जा रहे इस चुनाव का संबंध है, स्ट्रॉस काह्व की तो अब राजनीतिक रूप से यकीनन मृत्यु हो गई है। राष्ट्रपति सरकोजी और कार्ला ब्रूनी जुड़वां बच्चों के पैदा होने की उम्मीद लगाए हैं।

सरकोजी को मत सर्वेक्षणों में ३० प्रतिशत की बहुत न्यून रेटिंग मिली है और स्ट्रॉस काह्व कांड में उन्हें कुछ राहत जरूर मिलेगी क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी के पास काह्व के बराबर का अन्य कोई प्रभावी नेता नहीं है। उल्लेखनीय है कि फ्रांसीसी मीडिया में काह्व ने 'महान औरतबाज' के रूप में काफी बदनामी अर्जित की है और उनके लिए एक ही सम्मानजनक विकल्प बचा था और वह आईएमएफ के प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा। इसके बाद इस संस्थान का २४ सदस्यीय बोर्ड अगला फैसला लेगा और एशियाई देश खासकर चीन और भारत इस पद पर दावेदारी ठोकेंगे। वैश्विक स्तर पर बदले सत्ता संतुलन के मद्देनजर भी न्याय का तकाजा यही है कि यह पद एशियाई देशों को मिले। आईएमएफ का काम सिर्फ इतना ही नहीं कि वह संकट से जूझ रही यूरोपीय अर्थ व्यवस्थाओं के लिए राहत का प्रबंध करता रहे।

अमेरिका में आकर काम कर रही एक ३२ वर्षीय प्रवासी नौकरानी से छेड़छाड़ के आरोप में आईएमएफ के ताकतवर एमडी को ऐन उस समय हवाई अड्डे पर हिरासत में लेकर हथकड़ी पहनाई गई, उस वक्त वह जर्मन चांसलर से मीटिंग के लिए विमान पर सवार होने वाला था। उसे अमेरिका राइकर्ज द्वीप पर बनी जेल में बंद कर दिया गया है और हर १५ मिनट पर अधिकारी देखते हैं कि उसने कहीं आत्महत्या का प्रयास तो नहीं किया। मुझे हैरानी होती है कि क्या भारत, फ्रांस या अन्य किसी देश में ऐसा हो सकता था? खैर, इस बात के अलावा भी भविष्य में सोचने-करने को बहुत कुछ है। विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों ने ही निकट अतीत में शीर्ष पदों पर यौनाचार के आरोपों की मार झेली है और इनकी चयन प्रक्रिया में गंभीर लुटियां हैं। अमेरिका और यूरोप का इस पर एकछत्र प्रभुत्व चला आ रहा है, परंतु अब इसे बदलने का समय आ गया है।

पाकिस्तान में बेशक लादेन को अमेरिका द्वारा मार गिराने के संबंध में विवाद अभी भी जारी है, परंतु अमेरिका ने अपने ड्रोन हमले भी रोके नहीं हैं, पर्दे के पीछे वहां बहुत गतिविधियां चल रही हैं परंतु अमेरिका इस बार पाकिस्तान से नरमी से पेश नहीं आने वाला। मेरा मानना है कि ओसामा की तरह अन्य आतंकी नेता भी अलग-थलग पड़ रहे हैं और वैश्विक भाईचारा आतंक के विरुद्ध लड़ाई में जीतता जा रहा है।

कुछ बदले-बदले नजर आते हैं अन्ना हजारे

जंतर मंतर पर अपने अनशन के दौरान राजनीतिज्ञों को वहां फटकने की इजाजत नहीं देने वाले अन्ना हजारे अब लगता है कि खुद ही राजनीति करने लगे हैं। यह आश्चर्यजनक बात है कि लोकपाल विधेयक मसौदा पर उनके बयान अब कम और किसी राज्य सरकार के कामकाज पर उनकी प्रतिक्रिया ज्यादा सुनने को मिलती है। इतना ही नहीं अब तो वह सीधे केंद्र के सत्तारुढ़ गठबंधन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी खुलेआम निशाना साध रहे हैं। उन्होंने वक्तव्य है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो सीधे और ईमानदार आदमी हैं लेकिन रिमोट कंट्रोल (सोनिया गांधी) समस्याएं पैदा कर रहा है। लेकिन अन्ना यह बात कहने से पहले शायद वह यह भूल गये कि जब वह अनशन पर बैठे थे तब सबसे पहले सोनिया गांधी ने ही उन्हें पत्र लिखकर उनकी मांगों का समर्थन किया था जिस पर अन्ना ने सोनिया से अपनी सरकार को इस मुद्दे पर निर्देश देने की मांग की थी। सोनिया के निर्देश के बाद ही सरकार जागी और उसने जन लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने में समाज की भागीदारी को इजाजत एवं मंजूरीदी।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना हजारे की ओर से छेड़ी गई मुहिम को लोगों ने खूब समर्थन दिया लेकिन अब वही लोग अन्ना हजारे की पलटबयानी को लेकर हैरान परेशान हैं क्योंकि नेता अपनी बात से पलटते हैं तो उसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं लगता लेकिन जब गांधीवादी कार्यकर्ता ऐस करता है तो यह बात सोचने पर मजबूर करती है। कुछ दिनों पहले गुजरात और बिहार को विकास तथा अन्य मोर्चों पर सफल बताने वाले अन्ना को जब अपने इस बयान के लिए एक वर्ग के विरोध का सामना करना पड़ा तो उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। हालिया गुजरात दौरे में तो उन्हें राज्य में भ्रष्टाचार और प्रतिबंधित होने के बावजूद बड़ी मात्रा में शराब का अवैध व्यापार नजर आया। ऐसा ही कुछ उन्हें बिहार दौरे के समय भी नजर आए लेकिन क्या ऐसा करके अन्ना ने अपनी विश्वसनीयता को खत्म नहीं किया है? अनशन के दौरान अन्ना को जो देशव्यापी समर्थन मिला था उस पर खरा उतरने का उन्हें प्रयास करना चाहिए था जबकि वह राजनीति में उलझ रहे हैं या फिर कुछ लोगों की ओर से उन्हें उलझाए जा रहे हैं। लोकपाल विधेयक मसौदा तैयार करने को बनी सरकार और समाज की संयुक्त समिति की बैठकों के बाद कुछ बिंदुओं पर सहमति की बात कही जाती है लेकिन जनसभाओं में अन्ना कहते हैं कि विधेयक का मसौदा तैयार करने में सरकार के भीतर मौजूद लोग ही परेशानियाँ पैदा कर रहे हैं। अब बैठक के बाद दिये गये अन्ना के बयानों को सही मानें या फिर जन सभाओं में दिये गये अन्ना के बयानों को?

इसके अलावा इन दिनों भ्रष्टाचार मुद्दे पर सरकारों को आड़े हाथ लेने के लिए अन्ना विभिन्न राज्यों का दौरा भी कर रहे हैं। लेकिन दौरों के समय वह जिस प्रकार कुछ लोगों की ओर से नियंत्रित किये जा रहे हैं उससे संदेह पैदा होता है कि कहीं अन्ना का राजनीतिक दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा। हाल ही में उनके गुजरात दौरे के समय मीडिया में खबरें आईं कि कुछ छात्र उनसे मिलना चाहते थे और उन्होंने अन्ना से मिलने के लिए आग्रह भी किया था लेकिन कुछ लोगों ने छात्रों की चिट्ठी अन्ना तक पहुंचने ही नहीं दी। इसके अलावा अन्ना जिस तरह बार-बार सीधे सोनिया गांधी से संवाद करना चाहते हैं उससे भी लगता है कि मामला इतना साफ नहीं है जितना दूर से नजर आ रहा है। संयुक्त समिति में शामिल भूषण बंधुओं का सीडी मामला जब सामने आया था तब भी अन्ना ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर 'बदनाम करने की राजनीति को समर्थन' बंद करने को कहा था जिसके जवाब में सोनिया ने कहा था कि वह ऐसी राजनीति का समर्थन नहीं करतीं और आपको मेरी निष्ठा पर शक नहीं करना चाहिए। जाहिर है अन्ना यह बात समझ गये हैं कि सीधे सोनिया के साथ संवाद से जहां राजनीतिक, सामाजिक कद बढ़ता है वहीं इससे सरकार भी दबाव में आ जाती है। इसलिए शायद वह बार-बार इसी तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं।

दूसरी और, विचारधारा मुद्दे पर लोग भले शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे से इत्तेफाक नहीं रखते हों लेकिन उनकी इस बात में तो वाकई दम है कि अन्ना की मुहिम लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर हावी हो रही है जो कि ठीक नहीं है। अन्ना ने जो मुहिम छेड़ी थी वह तब पूर्ण रूप से सार्थक मानी जाती यदि वह शुरुआत की तरह राजनीति से कोई वास्ता नहीं रखते। लेकिन उन्होंने तो लोगों को अपनी राजनीति चमकाने की एक नई दिशा दिखा दी है। अब जल्द ही योग गुरुबाबा रामदेव भ्रष्टाचार और काला धन मुद्दे पर दिल्ली में अनशन पर बैठने जा रहे हैं। स्वत: जनसमर्थन न मिलने की आशंका से घिरे रामदेव के अनुयायी देश भर से लोगों को अनशन के समय दिल्ली लेकर आएंगे। जाहिर है यह सब भी सरकार पर दबाव बनाने की कवायद होगी। लेकिन इस सबसे क्या अनशन और आमरण अनशन जैसे गांधीवादी हथियारों की धार कम नहीं होगी?

बहरहाल, अब भी समय है कि अन्ना हजारे अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करे और स्वामी अग्निवेश, किरण बेदी, शांति भूषण, प्रशांत भूषण और अरविन्द केजरीवाल के अलावा अन्य बुद्धिजीवियों से भी संपर्क बढ़ाते हुए अपनी योजना को आगे बढ़ाएं। स्वामी अग्निवेश, शांति भूषण और प्रशांत भूषण जिस तरह विभिन्न विवादों में घिरे हैं उसे देखते हुए भी अन्ना हजारे को सोचना चाहिए कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध उन्होंने जो बड़ा अभियान छेड़ा है उसकी हवा कहीं उनके 'अपन' ही लोग न निकाल दें।